

3



छत्तीसगढ़ में 8
माह में अपराधों में
आई कमी

5



राजवीरों की
बात में इस बार
सीताराम येचुरी

7



परिवार नियोजन
का सटेश देगा
सारथी रथ

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 18

प्रति सोमवार, 16 सितंबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में जुटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव

पूर्व संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों को मिली सफलता, केंद्र ने दी प्रसाद योजना को मंजूरी

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
पटवार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साग राज्य में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने और पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करने के लिये निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य में नये स्तर से नीति तैयार करने का विचार करते हुए पिछले दिनों एक गहन चिंतन बैठक की। बैठक में प्रदेश के पर्यटन स्थलों को पर्यटकों की आवश्यकतानुसार विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है।

यह बैठक राज्य के नीति



आयोग के साथ की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वार्षिक रूप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। अटल नगर, नया रायपुर

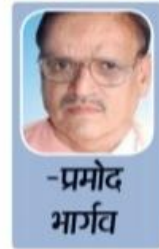
स्थित राज्य नीति आयोग के सभाकक्ष में समिति के सदस्यों ने इस विषय पर लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए। (शेष पेज 7 पर)

पर्यटन सर्किट बनाने पर जोर

बैठक में सदस्यों ने राज्य के पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास के लिए तथा पर्यटन की आवश्यकताओं के अनुसार नई योजना बनाने, नए पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित करने, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ट्राइबल थीम को लेते हुए टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास करने पर धिस्तुत चर्चा की। इसी प्रकार पर्यटन स्थलों में एडवेंचर गतिविधियों के विकास तथा निजी निवेशकों को आमंत्रित करने, बस्तर दर्राहरा, भोरमदेव महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, लोक मड़ई मेलों के आयोजन सहित अन्य स्थानीय महोत्सवों को बढ़ावा देने विचार विमर्श किया गया।

विशेष आलेख

नक्सलवाद से निर्णायक लड़ाई



-प्रमोद
भार्गव

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का संगठन अब सिमरता दिखाई दे रहा है। ऐसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सलवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। गृहमंत्री

अमित शाह ने रायगढ़ में कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है और इसे खत्म करने के लिए कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। केंद्र नक्सलवादी वामपंथी उग्रवाद का खाम्ता करने के लिए कृत संकल्पित है।

नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोशिश है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाए, जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। शाह का कहना है कि 2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। 2004-14 में नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में इन घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004-14 में 6,568 थी, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई है और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया है, उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निमूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है।

(शेष पेज 6 पर)

क्या मणिपुर और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति कायम करना चाहती है भाजपा?

आखिर क्यों इन दोनों स्थानों पर हस्तक्षेप कर मामले को शांत करते प्रधानमंत्री मोदी

-विजया पाठक

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से जल रहा है।

हाल ही में भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद भले ही वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा हो। लेकिन बांग्लादेश के बाद लगातार बंगाल और फिर मणिपुर की स्थिति को देखकर मन में कपकप असंतोष है। असंतोष इस बात का भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने अब तक न तो मणिपुर और न ही बंगाल के मामले में कुछ भी



कहना उचित समझा। मणिपुर को हमने और आपने पिछले एक साल स भी अधिक समय से जलते हुए देख रहे हैं। लाशें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं आपस में भिड़ रहे हैं लेकिन न



तो राज्य और न ही केंद्र सरकार अभी तक इसका कोई हल ढूढ़ पाई है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर यह सब कितने दिन और चलेगा। आखिर कब मोदी सरकार इस पूरे मामले को शांत करने में सफल होगी।

मुख्यमंत्री बिस्वा को दी गई है जिम्मेदारी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को मैतई और कुकी समुदाय के बीच खाई पाटने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है।

(शेष पेज 6 पर)

किसान न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने रेखा चौधरी को बनाया टीकमगढ़ जिले का प्रभारी

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. सागर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 20 सितंबर को निकाली जाने वाली प्रांतव्यापी किसान न्याय यात्रा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सागर जिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी को टीकमगढ़ जिले का प्रभारी बनाया है। वे जल्द ही अपने प्रभार जिला टीकमगढ़ के मुख्यालय पर पहुंचकर यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक लेंगी। मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में आगामी 20 सितंबर को जिला स्तर पर निकली जाने वाली किसान न्याययात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त यात्रा प्रभारी रेखा चौधरी शीघ्र ही टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचेंगी। वे



स्थानीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष व जिले के विधायकगण के साथ, पंचायत व नगरीय निकाय प्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं, जिला ब्लाक मंडलम वी सेक्टर कमेटीयों, सेवादल युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस एनएसयूआई किसान कांग्रेस आदि सभी विभागों प्रकोष्ठों व समितियों की बैठक लेंगी। (जगत फीचर्स)

स्टेशन की बाहरी चमक धमक से अधिक रेल सुविधा की दरकार

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. कटहलपुर। रेल्वे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत गाडवारा, करेली, नरसिंहपुर, गोटगाँव शामिल किया गया है। यह ठीक है किन्तु यात्रियों के बीच से निरन्तर यह बात समाने अति है कि नरसिंहपुर जिले में रेल सुविधाओं के विस्तार में उतनी रुचि नहीं दिखाई जाती जितनी कि होना चाहिए। स्टेशनों के बाहरी चमक आवरण को चमक भरा बना देने से यात्रियों को राहत नहीं मिलेगी। बल्कि लंबी दूरी की ट्रेनों के स्टॉपिज और नई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन एवं समयबद्ध तरीके से ट्रेनें चले तो यात्रियों के लिए यह आरामदायक होगा। यात्रियों की मांग तो यह है कि गाडवारा, करेली, गोटगाँव में गंगा

कावेरी, पवन एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेनों के स्टॉपिज अति आवश्यक है। व्यापारी, उद्योग पतियों, वकीलों, डॉ, छात्रों और किसानों के समय और धन की बाबंदी ना हो, वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधाएं नरसिंहपुर जिले की इन स्टेशन बॉचत हैं। शौचालयों, शॉड यात्रियों के लिए, बोहानी, सालीचौक, करकवेल में सुविधाओं होना चाहिए। मगर नहीं यहाँ पर यात्रियों को 12 से 14 घंटे तक कोई ट्रेनों का स्टॉपिज नहीं है। इटारसी और जवलपुर के बीच में दिन में दो राउन्ड पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग यहाँ की जनता समय समय पर उठाती रही है। परंतु जनप्रतिनिधियों और रेल्वे विभाग पर जू भी नहीं रंग रही है। (जगत फीचर्स)

कुएं में मिले बच्ची और तीन महिलाओं के शव

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. सागर। शनिवार सुबह कुएं में तीन महिलाओं और एक बच्ची का शव मिला है। इनमें दो महिलाएं फंटे पर लटकी मिलीं, जबकि अन्य महिला और बच्ची का शव पानी में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कुएं से निकलवाने के लिए एसडीआईआरएफ की टीम को बुलाया गया है। मामला देवरी थाना क्षेत्र के कोरा गांव का है। देवरी एसडीओपी शशिकंत सरयाम ने बताया कि महिलाओं की पहचान आरती लोधी (35), भारती लोधी (29), भागवती बाई (65) के रूप में हुई है। बच्ची का नाम रेंफिका लोधी (6) है, जो भारती की बेटी थी। भारती और आरती रिरते में देवरीनी जेठानी थीं। नानी भागवती लोधी और नातिन रेंफिका लोधी का शव पानी में मिला है। भागवती बाई भारती की मां थीं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद

ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

छोटी बहू ने किया था सुसाइड, आरती-भारती के प्रति जेल में है

परिवार के सदस्य सुरेंद्र लोधी ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे गांव के ही रहने वाले किशोर लोधी ने सुचना दी थी। इसके बाद सरपंच और पुलिस मौके को बताया। इस और गांव वालों के साथ मौके पर पहुंचे। सुरेंद्र ने बताया कि, 'एक साल पहले छोटे भाई सोनू लोधी की पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड किया था। मामले में पुलिस ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था। भारती और आरती के प्रति जेल में है। मायके वाले लगातार परेशान कर रहे थे। आर दिन भर आकर धमकी देते थे। मारपीट और गाली-गलबाज करते थे। शुक्रवार रात करीब 10 बजे भी घर आकर विवाद किया था। डर के मारे मैं रात में घर भी नहीं गया था। (जगत फीचर्स)



स्वभाव और संस्कारों में लाएं स्वच्छता

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 अंतर्गत स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता पर धार्मिक संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में नर्मदापुरम के सभी धार्मिक संगठनों के सदस्यों के साथ ही

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक एवं ब्लॉक समन्वयक सम्मिलित हुये। बैठक के दौरान रावत ने बताया कि शासन निर्माण के कार्य कर सकता है। परंतु मानसिकता में परिवर्तन कराने का कार्य धार्मिक संगठन ही कर सकता है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हमें व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इसके लिये

प्रशासनिक अमले के साथ साथ सभी के सहयोग की भी आवश्यकता है। बैठक के अंत में नर्मदा मंदिर सेठानी घाट के पुजारी गोपाल प्रसाद खड्डर ने कहा कि हमें सबसे पहले स्वयं की स्वच्छता अपनानी होगी। इसके बाद ही हम दूसरों को समझाशुश दे सकते हैं। श्री रावत द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।

सुरक्षा प्रबंधों में कोई चूक ना हो

-कैलाश चंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने विदिशा जिले की अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों सहित अन्य के लिए किए जाने वाले सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उक्त बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे। बैठक के प्रारंभ में मेडिकल कॉलेज के डीन मनीष निगम ने सुरक्षा के संबंध में किए गए प्रबंधों की बिन्दुवार जानकारीयों पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की।

संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा संबंधी प्रबंधों में कोई चूक ना हो का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा उपायों का सतत रिहर्सल करते रहे। उन्होंने रात्रिकालीन के दौरान सुरक्षा के उपायों पर विशेष बल देते हुए कहा कि सम्पूर्ण परिसर में उजाले के समुचित प्रबंध हो जिन क्षेत्रों के सीसी कैमरे बंद है उन्हें अक्लिम्ब ठीक कराया जाए। सुरक्षा गार्ड एक ही स्थल पर बैठे ना रहे बल्कि संबंधित

विंग में भ्रमण करते हुए चैककी नजर रखें।

संभागायुक्त सिंह ने बैठक में मौजूद चिकित्सकों एवं अन्य से संवाद कर सुरक्षा के उपायों में और क्या प्रबंध सुनिश्चित किए जाए पर सुझाव जाँने। उन्होंने जिन क्षेत्रों में बिजली ना होने की सुझावों पर शीघ्र अमल करने के निर्देश दिए तत्संबंध में लोक निर्माण विभाग की विद्युत शाखा की एसडीओ द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में बिजली संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक प्राक्कलन उपरांत टेण्डर स्वीकृत होने और कार्यों पर तीस लाख रूपए के लिए आटोनमस खण्ड से कार्यवाही करने की स्वीकृति पूर्व की बैठक में प्राप्त की गई है। उक्त कार्य शीघ्रतः शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा सीसी कैमरों के प्रसारण का कंट्रोल यूनिट पुलिस चैकी में स्थापित करने का सुझाव देते हुए कहा कि जगह-जगह साइन बोर्ड लगाए जाएं कि आप सीसी कैमरों की निगरानी में है। रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि महत्वपूर्ण नम्बर स्वयं के मोबाइल

में सेव करें वहाँ संकेतक स्थलों पर भी अंकित कराएं।

कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह ने मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के टूटिकोंग से किए जाने वाले प्रबंधों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया और महिला स्टाफ अकेले भ्रमण ना करें। एक खण्ड से दूसरे खण्ड जाना हो तो अपने साथ एक सहयोगी जरूर रखें। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के टूटिकोंग से आवश्यक गाडों के संबंध में डीन निगम ने बताया कि साठे तीन सौ बिस्तरों के हिसाब से सुरक्षाकर्मी तैनात है जबकि अब मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नौ सौ बिस्तरों में परिवर्तित हो गया है इस कारण से उन्होंने सुरक्षाकर्मीयों की संख्या बढ़ाने और रात्रि में महिला सुरक्षा गार्ड की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है।

संभागायुक्ता सिंह ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार सुरक्षाकर्मीयों की तैनाती हो इसके लिए आवश्यक प्रबंधक स्थानीय संसाधनों से पूर्ति कराए जाएँ और आवश्यक प्रस्तावों पर सहमति के उपरांत क्रियान्वयन करेंगे। (जगत फीचर्स)

छत्तीसगढ़ में 8 माह में अपराधों में आई कमी : सीएम विष्णुदेव साय

-संवाददाता

जगत प्रवाह, रायपुर। दो

दिवसीय बैठक के बाद सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुरासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इससे बीते सालों की तुलना में अपराध की संख्या में कमी आई है, इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि आखिरी दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आज ये बैठक चली है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी, एसोएस हेम, डीजीपी और सीनियर अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर और एसपी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान आईजी रंज, जिला कलेक्टर और एसपी ने अपने जिलों की स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि आज की बैठक में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात रखी गई है।

मुख्यमंत्री साय ने किया ये दावा

सीएम साय ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की पिछली सरकार और हमारे 8 महीने के सरकार के कार्यकाल की तुलना करें, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफी कम हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रदेश के सभी अधिकारी मन लगकर काम कर रहे हैं, उन्होंने आगे कहा कि सभी अधिकारी प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रखना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के समृद्ध विकास की चिंता कर रहे हैं।

अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश

इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट एक संदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा, "अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले, आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे, पुलिस थानों का वातावरण ऐसा हो कि आम नागरिक को थानों में प्रवेश करते समय सहयोग की उम्मीद हो, इसको लेकर पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सीएम साय ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "साथ ही प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर और एसपी के जरिये आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने, न्याय संहिता का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पुलिस को नए कानूनों के अनुरूप कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "हमारी सरकार प्रदेश में सुरासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पिछले सालों की तुलना में अपराध की संख्या में कमी आई है।" (जगत फीचर्स)



लिया भी निर्देशित किया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "हमारी सरकार प्रदेश में सुरासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पिछले सालों की तुलना में अपराध की संख्या में कमी आई है।" (जगत फीचर्स)

रायपुर के 10 वार्डों में किया 05 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन

-संवाददाता

जगत प्रवाह, रायपुर। पूर्व कैबिनेट

मंत्री और विधायक राजेश मूगत की अगुवाई में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन निर्माण कार्यों को मंजूरी मिल रही है। मूगत ने माधवराव सप्रे वार्ड में 90 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। मूगत ने बताया कि वह जनभावना के अनुरूप, मांग के आधार पर आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्रतिदिन अलग-अलग वार्डों में विकास कार्य स्वीकृत कर रहे हैं। वहीं बीते 5 दिनों में ही उन्होंने 10 वार्डों में 5 करोड़ रुपए का भूमिपूजन किया है। उन्होंने बताया कि रायपुर पश्चिम के विभिन्न वार्डों में सुविधाओं के विस्तार हेतु वह नागरिकों

से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा उनके कार्यालय में आने वाले आवेदनों को भी देख रहे हैं। इसी आधार पर वह अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। मूगत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाणा साधा उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ में विकास कार्य रुके हुए थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहलु गांधी अपने बयानों में खटखटा



शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन नेताओं की आपसी की खटपट ने भ्रष्टाचार करके झटपट पैसा कमाने की काली नियत ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल एक दिया। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ और है। कांग्रेस केवल कहती रही, लेकिन भाजपा की सरकार ने वाकई में खटखटा और सांघ सांघ कार्य करके दिखाया है। (जगत फीचर्स)

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच 53 नए मार्गों पर चलेगी यात्री बसें, दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक



-संवाददाता

जगत प्रवाह, रायपुर। छत्तीसगढ़

और मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच 53 नए मार्गों पर जल्दी ही यात्री बसें का संचालन होगा। यह यात्री बसें अंतरराज्यीय करार के अनुसार दोनों राज्यों के विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच चलेगी। इसके लिए दोनों राज्यों के परिवहन विभाग अधिकारियों की 17 साल बाद भोपाल में बैठक हुई। इस दौरान दोनों ही राज्यों के अधिकारियों की बीच सहमति बनी है। चिन्हकित मार्गों का सर्वे, पहले से चल रही वाहनों की संख्या, समय चक्र और संबंधित जिले के आरटीओ की रिपोर्ट मिलने के बाद परमिट जारी होगा। साथ ही दावा-आपत्तियों की सुनवाई कर निराकरण किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच यात्रियों की संख्या को देखते हुए पिछले काफी समय से इसकी कवायद चल रही थी। 2007 में

दोनों राज्यों के बीच हुए अंतरराज्यीय समझौते के तहत 87 बसों का संचालन किया जा रहा है। अतिरिक्त नई बसों के संचालन से यात्री सुविधा में विस्तार होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग सचिव एस प्रकाश के नेतृत्व में अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर, मनोज धुव और मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश की राजधानी जुड़ेगी

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मध्यप्रदेश के भोपाल के साथ ही इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, मंडला सहित अन्य प्रमुख जिलों के लिए बस चलेगी। इनको दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर धमतरी सहित अन्य प्रमुख शहरों से मध्यप्रदेश के संचालन किया जाएगा। बता दें कि इस समय रायपुर से

जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, मैहर सहित अन्य शहरों के लिए बसों का संचालन होता है।

महाराष्ट्र से होगा करार

छत्तीसगढ़ से नागपुर, गोंदिया और तुमसर के रास्ते होकर मध्यप्रदेश जाने वाली बसों के महाराष्ट्र परिवहन निगम के अधिकारियों से चर्चा होगी। समझौते के तहत तीनों राज्यों के बीच बसों के संचालन पर विचार किया गया है। बताया जाता है कि इसमें से अधिकांश राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग से होते हुए चलेगी। इससे तीनों ही राज्यों के यात्रियों के साथ ही राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा। बता दें कि इस समय रायपुर से मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा के लिए कवर्धा और राजनांदगांव के रास्ते संचालन होता है। समझौता होने के पर नागपुर से सावनेर के रास्ते चलाए जाने पर तीनों ही प्रमुख शहर जुड़ने से यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

एमएस भोपाल में जुलाई 2024 पीएचडी बैच के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कोर्सवर्क का शुभारंभ



-संवाददाता

जगत प्रवाह, भोपाल। सितंबर 2024

को जुलाई 2024 पीएचडी बैच के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कोर्स-वर्क का उद्घाटन किया गया। एमएस भोपाल के कार्यपालक निदेशक, प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह ने कहा कि पीएचडी कार्यक्रम के माध्यम से शोधकर्ताओं को समाज की मौजूदा चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शोध का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत अकादमिक उन्नति नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका समाज में वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। प्रोफेसर सिंह ने नए शोधार्थियों से कहा कि वे अपनी रुचियों के अनुसार शोध के क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। छात्रों को चाहिए कि वे ऐसे विषयों का चयन करें जो

समाज की समस्याओं को समझने और हल करने में सहायक हों और जो उनके क्षेत्र में वास्तविक प्रगति और नवाचार को बढ़ावा दें। उन्होंने संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करने के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि पीएचडी के दौरान नैतिकता और अनुशासन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉ. रंजित कौर कंवर, सहायक डीन (अनुसंधान) ने पीएचडी कार्यक्रम की व्यापक जानकारी प्रदान की और अनुसंधान के नैतिक मानकों, अनुशासन और उपलब्ध समर्थन प्रणाली की चर्चा की। इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में डीन (अनुसंधान), डीन (परीक्षा) और डीन (छात्र कल्याण) ने भी अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में 25 नए शोधार्थियों को शामिल किया गया, जिससे कुल पीएचडी छात्रों की संख्या 69 हो गई है, जो जून 2019 से शुरू हुई थी।

सम्पादकीय

आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण

हर साल लाखों लोग मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत चुनौतियों के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। आत्महत्या को लेकर जागरूकता बढ़ाने को लेकर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस बार इस दिवस की थीम है 'नैरेटिव बदलें' जोकि एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि आत्महत्या के बारे में हमारी सोच बदलने की जरूरत है। इस थीम का उद्देश्य आत्महत्या से जुड़े मिथकों को तोड़ना, जागरूकता बढ़ाना और समर्थन के लिए एक ऐसा माहौल का तैयार करना है जिससे आत्महत्याओं को रोका जा सके। इस सम्बन्ध में राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरफ से सभी जिलों को इस दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पत्र जारी किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक्सीडेंटल डेथ एवं सुसाइड रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की दर 3.5 है। राज्य में 2022 में कुल 8,176 आत्महत्याएँ दर्ज की गयी, जिसमें 5225 संख्या पुरुषों की रही, वही 2951 आत्महत्या महिलाओं द्वारा की गयी। जिसमें से 1631 आत्महत्या गृहिणियों की रही, 5162 शादीशुदा जोड़ों की, 1521 बेरोजगार व्यक्ति और 1060 छात्रों कि रही। यह दिखाता है कि सामाजिक और मानसिक दबाव, पारिवारिक समस्याएँ और वित्तीय तनाव आत्महत्याओं

के पीछे मुख्य कारण हैं।

आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र की संख्या 22,746 है वही तमिलनाडु में 19,834, मध्य प्रदेश में 15,386, कर्नाटक में 13,606, बंगाल में 12,669 में आत्महत्या के मामलों की संख्या रही। देश में होने वाली कुल आत्महत्या के मामलों में 49.3 प्रतिशत आँकड़े सिर्फ इन पाँच राज्यों से हैं। केजीएमयू के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल प्रोफेसर

डॉ. आदर्श त्रिपाठी बताते हैं कि लोग आत्महत्या का प्रयास आवेश में आकर करते हैं जैसे पारिवारिक झगड़े के बाद, लडाई, ब्रेकअप आदि अगर व्यक्ति कुछ फलों के लिए उस बात से भटक जाए तो ऐसा नहीं करते इसलिए सामान्यता सभी को यह सलाह ही जाती है कोई व्यक्ति यदि परेशान है तो उसकी बात सिर्फ सुन ली जाये। उसे यह जताएँ कि हम उसकी परिस्थिति को समझ रहे हैं। यह तरीका उस व्यक्ति के तनाव को कम करने में सहायक है। हमेशा परेशान व्यक्ति को अपनी राय देना ठीक नहीं है। आत्महत्या से जुड़े मुद्दों में सामाजिक दबाव और पारिवारिक कारण सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसमें लगभग 30 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान मानसिक बीमारियों का है जैसे डिप्रेशन, एंजायटी, सायकोटिक डिसऑर्डर, नरो के सम्बंधित बीमारियों जोकि आत्महत्या से सम्बंधित व्यवहार को बढ़ावा देती है। ऐसे में मानसिक बीमारियों की पहचान और सही समय पर इलाज करवाना भी सुसाइड के केंसेस को पर्याप्त ढंग से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।



सियासी गहमागहमी

शिवराज के नक्शे कदम पर चल रहे यादव?



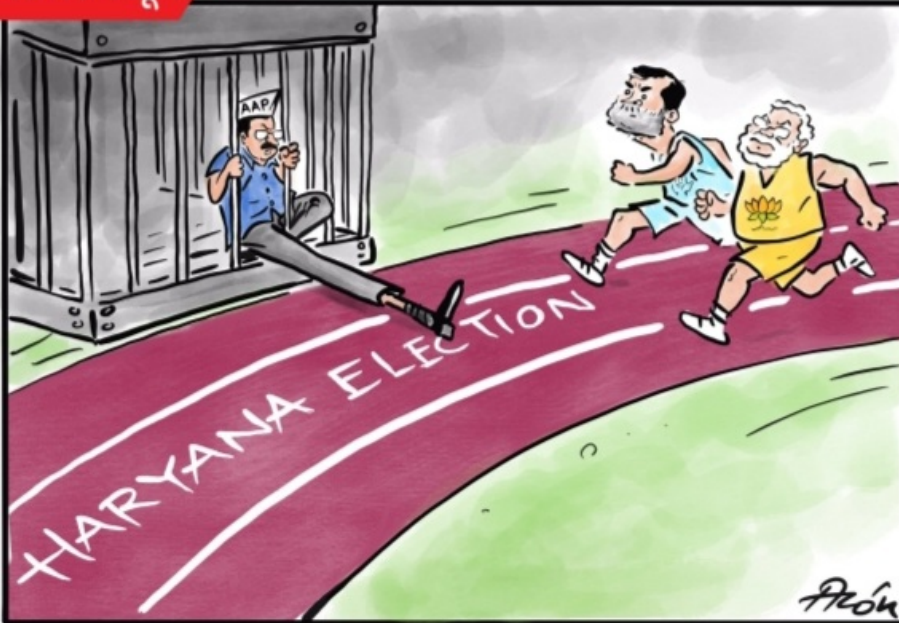
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि राज्य में उन्होंने एक भाई और मामा के स्वरूप में 18 वर्षों तक राज किया है। सत्ता की शक्ति होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर कभी भी सत्ता का गुरुर नहीं दिखाई दिया और वह उसी मिलनसार भाव से आमजन से मिलते रहे जैसे वह पहले मिलते थे। चौहान के इस कार्यशैली को देख अब मोहन यादव भी आगे बढ़े रहे हैं। आमजन से मिलना, उनसे चर्चा करना, उनसे बातचीत करना यह सब यादव की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यादव चाहते हैं कि वह प्रदेश की जनता के मन मस्तिष्क में बनी शिवराज सिंह चौहान की छवि को किसी तरह से बदल पायें लेकिन फिलहाल यह होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब आगे क्या-क्या पैंतरे अपनाते हैं।

सारंग के लिए आसान नहीं आगे की राह



नर्सिंग और पैरामेडिकल चोटाले में से उठ रहे धुंए की आंच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शिवराज खेमे के प्रमुख राजनेता विश्वास सारंग पर उठती दिखाई पड़ रही है। इससे लगने लगा है कि सारंग की आगे की राह आसान नहीं है। आलम यह है कि कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता अब सारंग द्वारा किये गये इस भ्रष्टाचार का विरोध विधानसभा से सड़कों तक करते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। विपक्षी नेताओं का लगातार विरोध सत्ता पक्ष के मुखिया के लिये कांटे की राह साबित हो रहा है। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कब प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दें। जाहिर है कि सारंग के ऊपर कोरोना संक्रमण के समय किये गये पैरामेडिकल और नर्सिंग चोटाले में सम्मिलित होने के आरोप लगे हुए हैं।

हफते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

मध्य प्रदेश में सेना के दो जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुकान पूरे सजाज को तर्नसार करने के लिए कायरी है।

भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है - और, महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत घिटाजनक।

-राहुल गांधी

कावेस वोट @RahulGandhi



मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023 में बलात्कार के मामलों में 66% की वृद्धि हुई है। प्रदेश ने हर रोज बलात्कार के 14 मामले दर्ज हो रहे हैं।



यह आँकड़े बताते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति फिरतनी टयनीय है।

-कमलनाथ

प्रदेश कावेस अक्टव

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

जेएनयू के छात्र से लेकर मार्क्सवादी राजनेता तक का प्रभावी सफर रहा है येचुरी का

समता पाठक/जगत प्रवाह



वर्तमान माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। येचुरी लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्हें एम्स में रेसिपेन्टरी सर्पोट पर रखा गया था। येचुरी को 19 अगस्त में सीने में संक्रमण के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। हलत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। उनकी पार्टी के मुलाबिक, डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रख रही थी।

मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ व पूर्व सांसद सीताराम येचुरी ने अपना शरीर डोनेट किया हुआ है। उन्होंने अपने शरीर को रिसर्च और टीचिंग के लिए डोनेट कर रखा है। इसलिए शनिवार यानी 14 सितंबर को उनका शरीर सीपीएम दफ्तर में लाया जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर से उनके पार्थिव शरीर को एम्स में लाया जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपना शरीर डोनेट कर रखा है। राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले सीताराम येचुरी की एक नहीं बल्कि दो शादी हुई थी। सीताराम येचुरी ने पहली शादी इंचाणी मजूमदार से की थी। लेकिन इसके बाद उनकी दूसरी शादी सोमा चिरतो से हुई थी। येचुरी एक भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और 1992 से सीपीआई के पोलिट ब्यूरो के सदस्य थे। वे 2005 से 2017 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद रहे थे।

येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को मद्रास में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता सर्वेचोर सोमयाजुला येचुरी और माता कल्पकम येचुरी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के मूल निवासी थे। उनके पिता आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इंजीनियर थे। उनकी मां एक सरकारी अधिकारी थीं। येचुरी हैदराबाद में पले-बढ़े। उन्होंने 10वीं कक्षा तक हैदराबाद के आर्ट्स संटर्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद 1969 के तेलंगाना आंदोलन ने सीताराम येचुरी को दिल्ली आने पर मजबूर कर दिया।

सीताराम येचुरी ने नई दिल्ली में प्रेसिडेंट एस्टेट स्कूल में दाखिला लिया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) की पढ़ाई की और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से अर्थशास्त्र में एमए किया। उन्होंने दोनों में प्रथम श्रेणी हासिल की। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के लिए जेएनयू में दाखिला लिया। निसे आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी के साथ रह कर दिया गया। येचुरी को 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, उस समय वे जेएनयू में छात्र थे। गिरफ्तारी से पहले वे कुछ समय के लिए भूमिगत रहे और आपातकाल के खिलाफ प्रतिक्रिया का आयोजन किया। आपातकाल के बाद, वे एक वर्ष (1977-78) के दौरान तीन बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। येचुरी ने प्रकाश करत के साथ मिलकर जेएनयू में चामपंधी गढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई। 1978 में सीताराम येचुरी को एसएफआई के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया और वे एसएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष बने। वे एसएफआई के पहले अध्यक्ष थे जो केरल या बंगाल से नहीं थे। इसके बाद 1984 में वे सीपीआई (एम) की केंद्रीय समिति के लिए चुने गए। 1985 में पार्टी संविधान को संशोधित किया गया और पांच सदस्यीय केंद्रीय सचिवालय चुना गया, जिसमें युवा दिग्गज शामिल थे।

पर्यावरण के प्रति उदासीनता के मायने



आज की बात प्रवीण कवकड़ स्वतंत्र लेखक

जगत प्रवाह, भोपाल।

जैसे-जैसे समय बीतता गया हमारी जरूरतें भी बढ़ती गईं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण के प्रति निर्दयता दिखाने लगे। हमने जनसंख्या वृद्धि पर पहले से रोक नहीं लगाई, जिससे लोगों को संसाधन कम पड़ने लगे और अत्यधिक रूप से पर्यावरण का विनाश होने लगा। गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, पेड़ पौधों और वनों का विनाश होने लगा, जीव जंतुओं को अपने फायदे के लिए मारा जाने लगा, हर तरह प्रदूषण फैल गया। जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान

पहुंचा।

पर्यावरण यानि ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से ढंकर रखता है, जो हमसे जुड़ा है और हम उससे जुड़े हैं और हम चाहें तो भी खुद को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। प्रकृति और पर्यावरण एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति या वस्तु चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, पर्यावरण के अन्तर्गत ही आती है। पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा कि गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकृति पर मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी माना जाता है। अतः पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही है। आज हम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालकर समाज को इसके लिए जागृत करना चाहते हैं।

पर्यावरण अर्थात् जिस वातावरण में हम रहते हैं। हमारे आस पास मौजूद हर एक चीज, जीव-जंतु, पक्षी, पेड़-पौधे, व्यक्ति इत्यादि सभी से मिलकर पर्यावरण की रचना होती है। हमारा इस पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है और हमेशा रहेगा। प्रकृति और पर्यावरण की अद्भुत सुंदरता देखते ही हृदय में खुशी और उत्साह का संचार होने लगता है। हरे भरे लहलहाते पेड़, आसमान में कलरव करते और चहचहाते पक्षी, जंगल में दौड़ते जीव जंतु, समन्दर में आती और जाती हुई लहरें, कल कल करके बहती हुई नदियां आदि जो मनोरम अहसास करावते हैं, वो हमें अन्य कहीं से महसूस नहीं हो सकता। फिर भी ये अफसोस की बात है कि लोग आज भी इसके महत्व को समझ नहीं पाए हैं और इसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वे यह नहीं जान पा रहे कि पर्यावरण की हानि करके वे अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। (जगत फीचर्स)

पर्यावरण की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा

जगत प्रवाह, भोपाल। गौतम चुड़

ने ढाई हजार साल पहले ही समझ लिया था कि "पर्यावरण की रक्षा: भविष्य की सुरक्षा" तभी तो उन्होंने पेड़, वायु, पर्वत एवं विभिन्न जल स्रोत- कुएँ, तालाब, झरने, नदी की शुचिता और संरक्षण को अपने प्रवचनों में विशेष स्थान दिया और अपने अनुयायियों को उसे सख्ती से अपनाने को कहा। आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण महज एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और तेजी से शहरीकरण के चलते पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति का आभास अब हमें होने लगा है, जब जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता का संकट और प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेज हो चुका है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे।



पर्यावरण की फ्रिड डॉ. प्रशांत सिक्का पर्यावरणविद्

मनुष्य सदियों से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता आया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह दूधम असंतुलित और अतिव्यक्त हो गया है। वन भूमि का अत्यधिक कटाव, नदियों और जल स्रोतों का दूषित होना, और वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण हमारी पृथ्वी खतरों में है। प्राकृतिक संसाधनों का यह अति प्रयोग न केवल पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है, बल्कि इसके दीर्घकालिक परिणाम हमारे जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कठिन हो जाएगा। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, जो औद्योगिकीकरण और वाहनों के अत्यधिक उपयोग से बढ़ रहा है, जलवायु को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और चरम मौसम को घटनाओं,

जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है। प्रकृति में सभी जीव-जंतु, वनस्पतियां और सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन मानव गतिविधियां, जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और शिकार, के कारण जैव विविधता में भारी गिरावट आ रही है। हर दिन सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं। यह संकट केवल उन जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन के कारण मनुष्य का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। अगर यह संकट इसी तरह जारी रहा, तो हमारी खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य प्रणाली भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। हमें यह समझने की जरूरत है कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार या किसी विशेष संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है। छोटी-छोटी आदतें जैसे पानी की बचत करना, जलजली का कम उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पुनः चक्रण (रीसाइकलिंग) को अपनाना, बड़े स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरणीय शिक्षा को अनिवार्य करना, जनसंचार माध्यमों के जरिए संदेश फैलाना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जागरूकता बढ़ाने के सशक्त उपाय हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ विकास करना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए टिकाऊ विकास को अवधारणा को अपनाना बेहद जरूरी है। टिकाऊ विकास वह है, जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। हमें ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और कृषि में टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत जैसे हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर हम न केवल पर्यावरण को रक्षा कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। इसके अलावा, अपशिष्ट प्रबंधन, पानी का पुनः उपयोग और स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना भी टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण

हिस्सा है। सरकारी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नीतियां और कानूनों को लागू करना चाहिए। वायु, जल और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौते, जैसे पेरिस समझौता, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इन समझौतों का प्रभावी कार्यान्वयन ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। विकासशील देशों को हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दी जानी चाहिए, ताकि वे आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा कर सकें। इसके साथ ही व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पौधारोपण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिए हम पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर भी हमें पहल करनी चाहिए। स्थानीय संगठनों और एनजीओ के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान, जल स्रोतों की सफाई और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा का सीधा संबंध हमारी आने वाली पीढ़ियों से है। जिस प्रकार से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अगर इसी गति से यह चलता रहा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इन संसाधनों से वंचित रह सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और इनका विवेकपूर्ण उपयोग ही हमारे भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। पर्यावरण की रक्षा केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें सरकार, उद्योग, समाज और व्यक्ति सभी की भागीदारी जरूरी है। हमारी धरती को सुरक्षित रखना न केवल आज की आवश्यकता है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उत्तरदायित्व भी है। अगर हम आज कदम नहीं उठाते, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः यह समय है कि हम सब मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संकल्प लें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकें। (जगत फीचर्स)

नक्सलवाद से निर्णायक लड़ाई



देकर नक्सलियों के विरुद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएँ भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

बस्तर के इस जंगली क्षेत्र में नक्सली नेता हिडमा का बोलबाला रहा है। वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा है, जबकि राज्य एवं केंद्र सरकार के पास मोदी सरकार से पहले रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति की हमेशा कमी रही थी। तथाकथित शहरी माओवादी बौद्धिकों के दबाव में भी मनमोहन सिंह सरकार रही। इस कारण भी इस समस्या का हल दूर की कौड़ी बना रहा। यही वजह थी कि नक्सली क्षेत्र में जब भी कोई विकास कार्य या चुनाव प्रक्रिया

संपन्न होती थी तो नक्सली उसमें रोड़ा अटक देते थे। नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दावा कर रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को झूठी दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुश विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र

कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध सलवा जुद्ध को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकासखण्ड के आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नतीजतन नक्सलियों की महेन्द्र कर्मा से दुष्मनी टन गई। इस हमले में महेन्द्र कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण पुक्कल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा अब फिर सत्ता में है। उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है, जो अब इनके सफाए के अंतिम चरण में है।

व्यवस्था बदलने के बहाने 1967 में पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलवादी ग्राम से यह खुनी आंदोलन शुरू हुआ था। तब इसे नए विचार और राजनीति का वाहक कुछ साम्यवादी नेता, समाजशास्त्री, अध्यापक और मानवाधिकारवादियों ने माना था। लेकिन अंततः माओवादी नक्सलवाद में बदला यह तथाकथित आंदोलन खून से इबारत लिखने का ही पर्याय बना हुआ है। जबकि इसके मूल उद्देश्यों में नौजवानों की बेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के सवाल पर कमजोर व निर्बलों का उत्थान, आंध्रप्रदेश और अविभाजित

मध्य-प्रदेश के आदिवासियों का कल्याण तथा राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर में आदिवासियों के प्रवेश शामिल थे। किंतु विश्रामा और पोषण से जुड़ी भूमण्डलीय आर्थिक उदारवादी नीतियों को जबर्न अमल में लाने की प्रक्रिया ने देश में एक बड़े लाल गलियारे का निर्माण कर दिया था, जो पशुपति नेपाल से तिरुपति आंध्रप्रदेश तक जाता है। इस पूरे क्षेत्र में माओवादी वाम चरमपंथ पसरा हुआ था। जब किसी भी किस्म का चरमपंथ राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना को चुनौती बन जाए तो जरूरी हो जाता है, कि उसे नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कारगर उपाय उचित हों, उनका उपयोग किया जाए?

हालांकि देश में तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा है, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक सुरक्षा देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुखा सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकांतिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संसद नहीं करतें हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब इस चरमपंथ पर अंकुश लगाता जा रहा है।

(जगत फीचर्स)

क्या मणिपुर और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति कायम करना चाहती है भाजपा

(पेज 1 का शेष)

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार... लेकिन फिर भी हिंसा जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार एक महीने से भी ज्यादा समय से जारी तनाव और हिंसा को क्रांति में नहीं कर पा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर के मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं?

लगातार दोरे दोरे रहे हैं फिर भी हालात खराब

गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के समय सभी पक्षों से बात कर 15 दिनों के भीतर शांति बहाल करने की अपील की थी लेकिन हालात और खराब ही होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह के क्रमद उठाए जाने की जरूरत थी वो क्रमद ना केंद्र सरकार ने उठाए ना ही राज्य सरकार ने। सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खूद करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए खूद हिंसा का ही सहारा ले रहे हैं।

मैतेई समुदाय शांतिपूर्वक रहते चले आए

विशेषज्ञ बताते हैं कि दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से मतभेद होने के बावजूद राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय शांतिपूर्वक रहते चले आए हैं। यहां तक कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी रहे हैं लेकिन

अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनका एक दूसरे से भरोसा ही उठ गया है। मणिपुर में अब कुकी बहुत इलाके में कोई मैतेई क्रमद रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर मैतेई लोगों के इलाके में जाने का जोखिम कोई कुकी नहीं लेना चाहोगे।

हिंसा का ये दौर नहीं घुमेगा

निम्नोम्बाम श्रीमा कहती हैं कि जब तक केंद्र सरकार बहुत मजबूती से दखल नहीं देती है और राज्य सरकार आम लोगों की सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं करती है, तब तक हिंसा का ये दौर नहीं थमेगा। राज्य में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता के. ओनील कहते हैं कि राज्य में जारी हिंसा से निपटने में जो गंभीरता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए थी वो उसने दिखाई नहीं। गृहमंत्री अमित शाह का मणिपुर दौर भी महज खानापूरी था। उन्होंने किन्हीं ठोस उपायों की बात की ही नहीं।

शांति समिति के गठन को स्वारिज किया

एक तरफ कुकी जनजाति की सर्वोच्च संस्था कुकी इंपी ने शांति समिति के गठन को खारिज किया है। वहीं, मैतेई समुदाय का नेतृत्व कर रही कोआर्डिनेटिंग कमेटी अर्थात मणिपुर इंटीग्रेटीड ने इस शांति कमेटी में शामिल नहीं होने को घोषणा की है। के. ओनील कहते हैं, "हालात सुधारने के मकसद से सरकार ने जिस शांति समिति का गठन किया उसमें उन्होंने अपनी मज्जा से लोगों को शामिल किया। इस समिति में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो राज्य के, इस इलाके के हालात का विशेषज्ञ हो। ऐसे लोग जो राज्य को ठीक से समझते हों उन्हें समिति में होना चाहिए था। तो इसी बात से

सरकार के इरादे समझ में आ जाते हैं।

जातीय विभाजन से उठी विंगारी

राज्य में मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच जो जातीय विभाजन हुआ है उसे पाटने की जिम्मेदारी अब हिमंत बिस्वा सरमा को सौंपी गई है। लेकिन मणिपुर में ही कई लोग इससे खुश नहीं हैं। मैतेई समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि हिमंत बिस्वा सरमा उत्तर पूर्वी राज्यों की आवाज के प्रतिनिधि नहीं हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि हिमंत बिस्वा सरमा पूर्वोत्तर के बड़े नेता हैं और वे इस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं।

सुरक्षा संबंधी दिक्कतों के साथ महंगाई

राज्य में हिंसा की वजह से आम लोगों को सुरक्षा संबंधी दिक्कतों के साथ महंगाई से भी जूझना पड़ रहा है। खाने-पीने की चीजों को क्रोमलत में जबरदस्त इलाक़ा हो गया है। लोगों को दवाइयों मिलने में परेशानी हो रही है। चावल कई जगहों पर दो सौ रुपए किलो तक मिल रहा है। एक महीने से जारी हिंसा के बावजूद अब तक सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है। कुकी जनजाति के सर्वोच्च छात्र निकाय कुकी छात्र संगठन ने इस पर नाराजगी जताई है कि पीएम चुप हैं।

प्रधानमंत्री तक ठीक से बात नहीं पहुंचाई

निम्नोम्बाम श्रीमा ने आगे कहा, "लोग मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बहुत खफ़ा हैं। उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ किया ही नहीं। मैतेई लोगों को इस

बात का गुस्सा है कि राज्य विधानसभा में 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं लेकिन इन विधायकों ने प्रधानमंत्री तक ठीक से बात नहीं पहुंचाई।

3 मई 2023 को शुरू हुई थी हिंसा

तीन मई को ये हिंसा तब शुरू हुई जब मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ राज्य के कुकी समेत दूसरे जनजातीय समुदाय ने रैली निकाली जो बाद में हिंसक हो गई। उन्होंने मैतेई समुदाय पर हमले किए। जवाब में मैतेई समुदाय ने भी अपनी बदले की कार्रवाई शुरू कर दी और मैतेई बहुत इलाकों में रह रहे कुकी समुदाय के लोगों के घर जला दिए गए और उन पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद मैतेई बहुत इलाकों में रहने वाले कुकी और कुकी बहुत इलाकों में रहने वाले मैतेई अपने-अपने घर छोड़कर जाने लगे।

संख्या में मैतेई लोग मारे जा रहे हैं

विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के पहाड़ी इलाकों से कुकी चरमपंथी मैतेई इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में मैतेई लोग मारे जा रहे हैं। राजधानी इंपाल तक में बेहद तनाव है। सीआरपीएफ के जवानों ने हमें सख्त हिदायत दी कि हम गाड़ी से बाहर ना निकलें। हिंसा का स्केल देखते हुए लगता है कि यहां कुकी और मैतेई समुदायों का आपसी रिश्ता है कि ही साथ ही लगता है कि बाहर से भी आए चरमपंथी हिंसा में शामिल हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हो सकते हैं। फिलहाल राज्य में 40 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इससे समझा जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं।

परिवार नियोजन का संदेश देगा सारथी रथ

17 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा

-अमित राय

जगत प्रवाह। बक्सर। जिला पदाधिकारी बक्सर, अरुण अग्रवाल के द्वारा जनसंख्या स्थिरिकरण के उद्देश्य से 13 सारथी रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले में 02 सितंबर से विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है। जिसके तहत 14 सितंबर तक दंपति संपर्क सप्ताह तथा 17 से 30 सितंबर तक पुरुष परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें इच्छुक लाभुक महिलाओं का बंध्याकरण के साथ साथ पुरुषों को नसबंदी भी की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग का विशेष ध्यान जनसंख्या स्थिरिकरण पर है।

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों को भी आगे आना होगा। ताकि सभी अपने परिवार के साथ समाज को भी खुशहाल बना सकें। उन्होंने बताया कि 12 प्रखंडों के लिए 12 सारथी रथ भेजे गए हैं। वहीं, 01 सारथी रथ सदर प्रखंड के शहरी



इलाकों में लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने में लगाया गया है। सभी सारथी रथ पर 01-01 आशा प्रतिनियुक्त है, जो लोगों के बीच परिवार नियोजन के असाई साधनों का विवरण करेगी। साथ ही, लोगों को पुरुष नसबंदी के लिए भी प्रेरित करेगी। प्रभारी सिविल सर्जन, बक्सर द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से लेकर

ग्राम स्तर तक लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में पंचायतों में पुरुषों को जागरूक करने के लिए सारथी रथ भी रवाना किया गया है। जिसके माध्यम से पुरुषों को जनसंख्या स्थिरिकरण को लेकर परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी दोनों साधनों के प्रति जानकारी दी जाएगी। ताकि

अधिक से अधिक पुरुषों को नियोजन के स्थायी साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। परिवार नियोजन में महिलाओं के साथ पुरुषों की भी अहम भूमिका होती है। दो बच्चों के बाद यदि किसी कारण से महिला नसबंदी नहीं कर सकती है तो पुरुष को नसबंदी करा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्हें

प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। साथ ही, पुरुष नसबंदी महिलाओं के बंध्याकरण से 20 गुना अधिक सरल और सुलभ है। प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया कि पुरुष नसबंदी और महिला बंध्याकरण के लिए लाभुकों को सारथी रथ के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। सारथी रथ शहरी और ग्रामीण चौराहों पर खड़ा कर परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। पखवाड़ा में हर स्वास्थ्य केंद्र के लिए पुरुष नसबंदी के कर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित अर्धघंटे में पुरुष नसबंदी लक्ष्य पूरा करना है। उन्होंने बताया कि पुरुष नसबंदी कराने पर व्यक्ति को 3000 हजार रुपये और प्रेक को 400 रुपये प्रोत्साहन धनराशि तत्काल मिलता है। महिला नसबंदी कराने पर 2000 महिला को और प्रेक को 300 रुपये मिलते हैं। प्रसव के बाद तत्काल महिला नसबंदी पर 3000 रूप्य और प्रेक को 400 रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। इसके अलावा अंतरा इंजेक्शन और आईयूसडी पर भी प्रोत्साहन धनराशि की सुविधा है। (जगत फीचर्स)

जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में जुटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव

(पेज 1 का शेष)

हर क्षेत्र में विकास कार्यों पर जोर

इसी तरह हस्त शिल्पियों को आकर्षक बाजार उपलब्ध कराने, संगीत और नृत्य के कलाकारों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने, स्थानीय तीज-त्योहारों, स्थानीय साहित्य, लोक कथाओं और ज्ञान को संरक्षित करने पर गहन विचार किया गया। स्थानीय खान-पान और तकनीकों को संरक्षण तथा नवाचार के लिए प्रोत्साहन, रचनात्मकता और कला कौशल के विकास सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है, इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं।

नीति दस्तावेज में शामिल करने सुझाव

बैठक में सदस्य के. सुब्रमण्यम ने छत्तीसगढ़ में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने, पर्यटन से राज्य की जीडीपी में योगदान बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, पर्यटन सुविधाओं के सुदृढीकरण और विकास तथा मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग अभियान को नीति दस्तावेज में शामिल करने सुझाव दिए। बैठक में राज्य की जनजातिय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने, राज्य में उपलब्ध वनसंपत्तियों और जीवों से युक्त विशाल वन क्षेत्र को पर्यावरण पर्यटन के रूप में विकसित करने, वैल्यूएड टूरिज्म, कृषि पर्यटन एवं मनोरंजन पार्क विकसित करने, टिकाऊ, समावेशी और जिम्मेदार पर्यटन, छत्तीसगढ़ को प्रमुख पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने, पर्यटन केंद्रों को संचालित करने स्थानीय समुदायों

को सशक्त बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने तथा छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित राज्य के रूप में प्रचार-प्रसार करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय धरोहर बनाने पर हो रही पहल

छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इसके लिए आपको पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना देश अभियान में हिस्सा लेना होगा। इस अभियान में हिस्सा लेकर आप अपने पसंद के पर्यटन स्थल को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर राष्ट्रीय धरोहर बना सकते हैं। साथ ही प्रदेश के अद्वितीय और खूबसूरत स्थलों को इस राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का यह एक सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों को पूरे देश में पहचान दिलाने का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने राज्य के गंतव्यों के लिए वोट करें और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

धरती रामकथा से जुड़ी है

सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। बलरामपुर जिले के तातापानी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा- तातापानी की धरती बहुत पवित्र धरती है। यह धरती रामकथा से जुड़ी है। तातापानी महोत्सव का आरंभ हमारी सरकार ने ही किया था। इसके बाद हर साल यह महोत्सव भव्य रूप लेता जा रहा है। तातापानी को पर्यटन स्थल के रूप में मैं घोषित करता हूँ। यहां पर्यटन विभाग का मोटल आरंभ करेगी। तातापानी क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में मास्टर प्लान भी

तैयार किया जाएगा।

सीएम ने कहा हर वादे को पूरा करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि तातापानी का संबंध माता सीता से है। यह बहुत पवित्र स्थल है। यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप सभी वायदे पूरा करेंगे। क्षेत्र की जो मांगें हैं उन्हें भी पूरा करेंगे।

भगवान राम के आगमन की भव्य तैयारी करना है

जाहिर है कि राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित करने में पूर्व संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की दृष्टि भी रही है। उन्होंने रमन सरकार के समय राज्य के हित में कई फैसले किये उसी क्रम में तातापानी का विकास भी शामिल है। अग्रवाल के अनुसार हमारा सौभाग्य है कि हमने ही 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय में तातापानी महोत्सव की शुरुआत की थी। हमारी आस्था के केंद्रों के विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रभु राम 22 तारीख को आ रहे हैं। उनके आगमन की भव्य तैयारी करनी है।

बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों को मिली सफलता

पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री एवं वर्तमान में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ को आस्था का केंद्र और धार्मिक पर्यटन के रूप में विश्व में पहचान दिलाने के प्रयासों के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। निदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार रोशन एम थॉमस ने पत्र

जारी करते हुए जानकारी दी है कि, राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर निर्माण, रायपुर के पुरखौती मुक्तानग में कन्वेशन सेंटर निर्माण, सिरपुर स्थित बागेरवती मंदिर का जीर्णोद्धार को प्रसाद योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही पांच प्रमुख शक्तिपीठों रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहसन, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी और सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर के विकास और उनको जोड़ने के लिए भी केंद्र से स्वीकृति प्रदान की है।

पहले ही 48.44 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके

पत्र के अनुसार मंत्रालय, पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)" और "स्वदेश दर्शन" के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। जिसके लिए डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी माता मंदिर को पहले ही 48.44 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर और जरापुर-कुनकुरी-मैनपाट कमलेशपुर-महेशपुर-कुदरार सरोधादादर-गंगोल-कोंडागांव-निथियानवागांव-जगदलपुर चित्रकोट, तीर्थगढ़, के विकास के लिए 96.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 2 अन्य गंतव्यों को भी चिन्हित किया गया है। जिसके लिए मंत्रालय द्वारा परियोजना विकास प्रबंधन सलाहकार की चयन प्रक्रिया जारी है। निदेशक, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरा प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य में चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।



विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन से विकास की नई राह...

- ❖ कृषक उन्नति योजना : धान का प्रति बिंदेल 3100 रुपये मिल रहा दाम, खेती-किसानी से खुले समृद्धि के द्वार
- ❖ मुख्यमंत्री आवास योजना (वागीण): 47 हजार 90 आवासहीन वागीण परिवारों को मिलेगा लाभ

- ❖ शासकीय भर्ती में आयु सीमा में छूट: पुलिस विभाग सहित शासकीय भर्तियों में युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
- ❖ शरावार मुक्त पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित



- ❖ मुफ्त अनाज: छत्तीसगढ़ के 68 लाख गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक निःशुल्क राशन
- ❖ वैदपता संग्राहक पारिश्रमिक: 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बीटा

- ❖ 'नियद मैल्लानार' अभियान के साथ नक्सल समस्या के पूर्ण निदान के प्रभावी कदम
- ❖ त्वरित निर्णय, सरल प्रशासन: विष्णु देव सरकार में अब तक 150 जाओवादी मुठभेड़ में डेर, 599 की गिरफ्तारी, 510 ने किया आत्मसमर्पण

RO No. 12929/1

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें...

हमने बनाया है, हम ही सँवारेगे



Visit us : [ChhattisgarhCMO](https://www.chhattisgarhcmo.gov.in) [ChhattisgarhCMO](https://www.chhattisgarhcmo.gov.in) [ChhattisgarhCMO](https://www.chhattisgarhcmo.gov.in) [ChhattisgarhCMO](https://www.chhattisgarhcmo.gov.in) [DPRChhattisgarh](https://www.dprchhattisgarh.gov.in) [DPRChhattisgarh](https://www.dprchhattisgarh.gov.in) www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़
समाज सेवा संस्थान